इन्वेस्ट नॉर्थ– सीआईआई इन्वेस्टमेंट कॉनक्लेव– नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश ने निवेशकों को राज्य में आने का दिया आमंत्रण

- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग– *उत्तर प्रदेश सरकार निवेश व उद्यम के माहौल को बेहतर बनाने के लिए पारदर्शी रूप से कटिबद्ध है।"*

नई दिल्ली/ लखनऊ, 24 जुलाई, 2014:

उत्तर भारतीय राज्यों का निवेश सम्मेलन–*इन्वेस्ट नॉर्थ* आज नई दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज़ (सीआईआई) के उत्तरी क्षेत्र के उपाध्यक्ष श्रीकान्त सोमानी के उद्घाटन भाषण से प्रारम्भ हुआ। सीआईआई द्वारा पार्टनर राज्यों के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सहित हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखण्ड भाग ले रहे हैं। इसमें भारतीय व 20 अंतर्राष्ट्रीय बिज़नेस एसोसिएशन्स हिस्सा ले रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च–स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व कर रहे राज्य के प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडीडी), संजीव सरन ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों को उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।

उत्तर प्रदेश पर आधारित विशेष सत्र 'एडवांटेज उत्तर प्रदेश–इनेबलिंग बिज़नेस इन्वायरनमेंट एण्ड प्रोजेक्ट्स फॉर इन्वेस्टमेंट' में उपस्थित निवेशकों व कई बिज़नेस समूहों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा– "विशाल उपभोक्ता आधार, तेजी से सुधरता हुआ इन्फ्रास्ट्रक्चर, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का केन्द्र तथा सुधारोन्मुखी सक्रिय शासन के परिणामस्वरूप राज्य तेजी से प्रगति के नये आयाम स्थापित करने की ओर अग्रसर है।"

राज्य में उपलब्ध दक्ष मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और तेजी से विकसित हो रही उच्चस्तरीय अवस्थापना परियोजनाओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से जोड़ना, विद्युत उत्पादन में 10,000 मेगावाट से 23,000 मेगावाट की वृद्धि, ग्रेटर नोएडा में रु 26,000 करोड़ के निवेश से सेमी कन्डक्टर बनाने की फैब इकाई, 4 जी नेटवर्क की स्थापना, कौशल विकास मिशन में 46 लाख पंजीकरण कुछ ऐसे संकेतक हैं जो अत्यन्त सकारात्मक एवं सम्भावनाओं से परिपूर्ण हैं।

प्रमुख सचिव, आईआईडीडी ने बताया कि कि वेस्टर्न एवं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर पर क्रमशः दिल्ली–मुम्बई इंडस्ट्रीयल कोरीडोर एवं अमृतसर–कोलकता इंडस्ट्रीयल कोरीडोर के विकास का क्रियान्वयन पूरी तेजी से शुरू कर दिया गया उन्होंने कहा– *"अमृतसर–दिल्ली–कोलकता इंडस्ट्रीयल कोरीडोर राज्य के औद्योगिक विकास की धूरी सिद्ध होगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है तथा पूरी होने वाली है, जबकि डीएमआईसी पर तीन अर्लीबर्ड परियोजनाओं– दादरी में मल्टी–मोडल लॉजिस्टिक्स हब, बोकाडी में मल्टी–मोडल ट्रांस्पोर्ट हब एवं ग्रेटर नोएडा में हाईटेक इंडस्ट्रीयल टाउनशिप पर कार्य प्रारम्भ हो गया है।"*

उत्तर प्रदेश केन्द्रित विशेष सत्र– 'एडवान्टेज उत्तर प्रदेशः इनेबलिंग बिज़नेस इनवाइरनमेंट एण्ड प्रोजेक्ट्स फॉर इंवेस्टमेंट' में बोलते हुए प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग–डॉ. शिव प्रताप सिंह ने राज्य में निवेशकों के लिए असीम सम्भावनाओं व विकसित की जा रही सरल व्यवस्था जिससे इन सम्भावनाओं को मूर्त रूप दिया जा सके पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा– *"उत्तर प्रदेश तेजी से औद्योगिक प्रगति कर रहा है, निवेश व उद्यम के माहौल को बेहतर बनाने के लिए न केवल राज्य की नीतियों व नियमों को बनाया जा रहा है अपितु चुनौती का सामना जमीनी स्तर पर कर रहे हैं"।*

प्रमुख सचिव– ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत, जीवेश नन्दन ने सौर ऊर्जा नीति के मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राज्य में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाये गए हैं, जिसके क्रम में 300 मेगावाट की निविदायें आमंत्रित की गई हैं, जो अवस्थापना के क्षेत्र में अनुभव वाले सभी विकासकर्ताओं के लिए खुली है।

एमडी, यूपीउसआईडीसी, मनोज सिंह ने निगम द्वारा विकसित या विकसित किए जा रहे नये औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में बताया। प्लास्टिक सिटी औरैया, ट्रांस–गंगा औद्योगिक क्षेत्र, कानपुर, फतेहपुर टेक्सटाइल पार्क आदि विकास के विभिन्न चरणों में हैं। उन्होंने बताया कि यूपीएसआईडीसी तथा फिल्म कलाकार संजय खान संयुक्त रूप से आगरा में थीम पार्क की स्थापना करेंगे जो अपनी तरह का पहला तथा पर्यटन की दृष्टि से आगरा का दूसरा आकर्षण होगा।

प्रदेश में अपने उद्यमों की सफल एवं प्रगति गाथा सुनाते हुए टाटा कन्सल्टेन्सी के जयन्त कृष्णा तथा पी टी सी इण्डस्ट्रीज़ के सचिन अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण व नये कदमों

की भूरी–भूरी प्रशंसा की। जयन्त कृष्णा ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा विचार है जिसका समय आ गया है। कोई कारण नहीं है कि देश में दूसरा सबसे अधिक जीडीपी वाला राज्य औद्योगिक विकास न करे।

प्रतिभागियों एवं राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों के मध्य पारस्परिक संवाद भी हुआ, जिसमें उद्योगों को उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं से अवगत् कराया गया। प्रमुख रूप से सौर ऊर्जा, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, श्रम, उच्च एवं चिकित्सा शिक्षा, आदि क्षेत्रों के विषय में चर्चा हुई। अवसर का लाभ उठाते हुए राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों ने नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित निवेश सम्मेलन में हस्ताक्षरित एमओयू करने वाले निवेशकों से भी भेंट कर उनका परियोजनाओं के बाबत बात की।

प्रमुख सचिव, श्रम–शैलेश कृष्ण, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य–अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण–अरूण सिंहल, अध्यक्ष नोएडा, ग्रेटर नोएडा–रमा रमन, प्रबन्ध निदेशक यूपीएसआईडीसी–मनोज सिंह, विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास–सुश्री कंचन वर्मा आदि अधिकारियों ने निवेशकों की जिज्ञासाओं के उत्तर दिए।